

आयात-निर्यात की लागत और घटाने की तैयारी

राहत

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कस्टम विभाग में विदेश से आने और निर्यात के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाने वाले माल का तत्काल क्लीयरेंस कराने की तैयारी कर रही है।

- कस्टम में सामान फंसने की लागत भी जुड़ जाती है
- घंटे भर में क्लीयरेंस देने के लिए बन रहा प्रोजेक्ट

सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है कि घंटे भर में ही क्लीयरेंस हो जाया करे। मामले से जुड़े

अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं सुझावों की व्यावहारिकता जांचने के बाद नीति बनाकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। मौजूदा दौर में कारोबारियों की लागत में कस्टम में सामान फंसने की भी लागत जुड़ जाती है। इसके कम होने से न केवल देश में आयात कच्चा माल कुछ सस्ता हो

जाएगा बल्कि निर्यात किया जाने वाला उत्पाद भी प्रतिस्पर्धा में खरा उतर सके। कारोबारियों के लिए कस्टम से सामान छुड़ाना बड़ी चुनौती होती है। इसमें न केवल पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, बल्कि समय भी बर्बाद होता है। वित्तमंत्रालय की तरफ से तैयार किए जा रहे कस्टम वन नाम से प्रस्ताव को आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।